Guidelines for Formation of State Fisheries Corporations

*210. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) Whether any guidelines have been issued by Central Government to various States for formation of fisheries corporations in States; and

(b) What steps have been taken by States in this regard ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH). (a) and (b) No, Sir. However, in accordance with the conditions of the World Bank under Inland Fisheries Project, five Fish Seed Development Corporations have been set up in the States of Bihar, West Bengal, Orissa, Uttar Pradesh and Madhya pradesh.

The Government have separately written to maritime States to activate their public sector Fisheries Corporations to uudertake deep sea fishing.

Fishing Harbour at Calicut

*211. SHRI E. K. IMBICHIBAVA : Will be Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal for construction of a fishing harbour in Putiyappa at Calicut; and

(b) if so, action taken thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) and (b) Project report for a fishing harbour at Puthiappa near Calicut, prepared by the Pre-investment Survey of fishing Harbours, was received in the Ministry in November 1982 and the same has been sent to the Government of Kerala for their comments.

राजस्थान में कोटा चम्बल कृषि विकास प्रियोजना के लिए केन्द्र द्वारा दिया गया धन

*212. **श्री चतुर्भुज** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान की कोटा चम्बल कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत 1983-84 में कितना धन दिया जाएगा तथा इसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा;

(ख) राज्य सरकार इस परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितना और किस प्रकार का सहयोग प्रदान कर रही है; और

(ग) क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री ने 12 जुलाई को कोटा में कहा था कि उक्त चम्बल कृषि विकास परियोजना के दूसरे चरण का काम हाथ में लिया जाना केन्द्र सरकार की स्वीकृति तथा सहयोग पर निर्भर करेगा; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा यह परियोजना कब और किस रूप में अनुमोदित की जायेगी तथा तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री : (**श्री राम निवास मिर्धा**): (क) और (ख) केन्द्रीय स्तर पर राज्य-वार अथवा परियोजना-वार प्रावधान नहीं किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता स्वीकार्य मदों पर किए गए खर्च के आधार पर रिलीज की जाती है। राज्य सरकार के अनुसार, उनके द्वारा परिकल्पित कार्यों की मदों से उन्हें 1983-84 में लगभग 80.10 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सकेगी ।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, चम्बल परियोजना का सम्पूर्ण कमान क्षेत्र पहले ही सम्मिलित है। कमान क्षेत्र विकास, जो 1974-75 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना चरण-एक के रूप में आरभं किया गया था, से संबद्ध कार्य की मदें जून, 1982 में पूरी कर ली गई थीं। परियोजना का चरण-दो भी राज्य द्वारा तैयार किया गया है। चरण-एक